

Rajasthan has been ranked among top 5 states on USHA ranking under the PM Scheme.



A review meeting was chaired by Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa at the Secretariat, Jaipur, on May 22, 2021, for both the Higher Education and Technical Education Departments. The meeting was dedicated to the implementation of the Budget Announcements 2025–26, enhancement of quality of higher educations, technical education enhancement and job creation through skill formation. The state government has a goal of developing students' abilities and linking them to jobs, Dr. Bairwa said. Rajasthan has been doing well under the Higher Education Campaign of the Prime Minister and has been included in the top 5 states of the country in PM-USHA.

Key Highlights

- Rajasthan is ranked in the top 5 states of the country in PM-USHA.
- The development works under PM-USHA in universities/colleges are now being directed for speedy completion.
- The progress of Swami Vivekananda Scholarship, Scooty Distribution Scheme and other higher education schemes was reviewed.
- The Deputy Chief Minister inspected the progress made on ground level in the MoUs which were signed by various institutions with the Technical Education Department.

- Academic and non-academic vacancies in government colleges were filled up at the earliest with directions.
- The work plan of Rajasthan College Education Society was reviewed for extension and administration of higher education as well.

The Review Meeting aims to:

Improving Higher Education Quality

- For the enhancement of quality of education in Universities and colleges.
- To make sure the development works are completed within time frame as per PM-USHA.
- To build up the support of welfare schemes for students.

Strengthening Technical Education

- To finish the construction of the Technical University building on time.
- To provide high quality infrastructure for improved academic and research facilities.
- To create innovative infrastructure for higher technical education.

Promoting Innovation and Startups

- To promote start-ups in the technical industry.
- To develop an entrepreneurial atmosphere at the technical universities.
- To offer resources, technical support and guidance to startups.

Significance for Rajasthan

This review meeting is significant from the perspective of the RAS examination as it links between higher education, technical education, skill development, generation of employment and promotion of startups. Rajasthan's performance in the areas of higher education infrastructure, governance is improving and has put the state in the top 5 under PM-Usha. The emphasis on empty positions, student welfare programs, technical university facilities and startups illustrates how the state government is attempting to connect education and employability with innovation.

Conclusion

The review meeting presided by Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa shows that Rajasthan is striving to reach a quality higher education and strong technical infrastructure and skill based employment. It is noteworthy to mention that Rajasthan has been included in the top 5 states under PM-USHA which is of great significance to the education sector in Rajasthan. Meeting project deadlines, filling the gaps in jobs and nurturing start-ups can help enhance the entire education landscape of Rajasthan.

MCOs

1. According to PM-USHA ranking, the state of Rajasthan will be categorized under which category of the states?

- A. Bottom 5 states in the country
- B. Top 5 states in the country
- C. Top 10 states in Asia
- D. It is the first state in India for all the indicators of education.

Answer: B

Explanation: Rajasthan is also included in the list of top five states of the country in Higher Education Campaign under the Prime Minister. This is significant as it is related to the state's performance in development works relating to higher education and in governance. The review meeting also emphasized the need to complete the works of PM-USHA in the universities and colleges in a short span of time.

2. What was the main concern discussed in the review meeting by the Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa?

- A. To cut-down the fund allocation to government colleges
- B. To improve students skills and the job opportunities are provided.
- C. To prevent any scholarship schemes in higher education institutions.
- D. To establish Private Universities instead of Technical Universities

Answer: B

Explanation : The State government aims to enhance the abilities of children and give them jobs, Dr Premchand Bairwa said. This connects Higher education and Technical education to employability. The meeting was also focused on the enhancement of infrastructure, completion of development works, student schemes and encouragement of startups in the technical field.

3. Which of the following issues was specifically reviewed during the meeting?

- A. Swami Vivekananda Scholarship and Scooty Distribution Scheme
- B. Only road construction projects
- C. Agricultural irrigation schemes only
- D. Tourism development in desert districts only

Answer: A

Explanation : During the review meeting, the activities of the schemes operated by the Higher Education Department, such as Swami Vivekananda Scholarship, Scooty Distribution Scheme were discussed. The Deputy Chief Minister also looked into the work of PM-USHA, MoUs in technical education, work programme of the Rajasthan College Education Society, vacant posts in government colleges and promotion of startups in technical institutions.

राजस्थान में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभागों की समीक्षा और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का प्रदर्शन

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बजट घोषणाओं 2025-26 की क्रियान्विति, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया है और राज्य देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की रैंकिंग में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत चल रहे विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
- स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण योजना और उच्च शिक्षा से जुड़ी अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
- तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए समझौता ज्ञापनों की जमीनी प्रगति की जानकारी ली गई।
- राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए।
- उच्च शिक्षा के विस्तार और प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी की कार्ययोजना की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के उद्देश्य

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना।
- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विकास कार्यों को समय पर पूरा कराना।

- विद्यार्थियों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करना।

तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाना

- तकनीकी विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना।
- बेहतर शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अधोसंरचना उपलब्ध कराना।
- आधुनिक तकनीकी शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अधोसंरचना विकसित करना।

नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा

- तकनीकी क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना।
- तकनीकी विश्वविद्यालयों में नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- स्टार्टअप को मार्गदर्शन, संसाधन और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना।

राजस्थान के लिए महत्त्व

यह समीक्षा बैठक राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और स्टार्टअप प्रोत्साहन को एक साथ जोड़ती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में राजस्थान का शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होना उच्च शिक्षा अधोसंरचना और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन को दर्शाता है। रिक्त पदों की पूर्ति, विद्यार्थी कल्याण योजनाओं, तकनीकी विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर राज्य सरकार के शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने के प्रयास को दिखाता है।

निष्कर्ष

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, मजबूत तकनीकी अधोसंरचना और कौशल आधारित रोजगार पर राज्य सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट करती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में राजस्थान का शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होना राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, रिक्त पदों को भरना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना राजस्थान के शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर सकता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की रैंकिंग में राजस्थान किस श्रेणी में शामिल हुआ है?

- A. देश के निचले 5 राज्यों में
- B. देश के शीर्ष 5 राज्यों में
- C. एशिया के शीर्ष 10 राज्यों में
- D. शिक्षा के सभी संकेतकों में भारत का प्रथम राज्य

उत्तर: B

व्याख्या: राजस्थान प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है। यह उपलब्धि उच्च शिक्षा से जुड़े विकास कार्यों और प्रशासनिक प्रदर्शन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया गया।

2. समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने किस मुख्य उद्देश्य पर जोर दिया?

- A. राजकीय महाविद्यालयों की संख्या घटाना
- B. विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
- C. उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करना
- D. तकनीकी विश्वविद्यालयों के स्थान पर निजी संस्थान स्थापित करना

उत्तर: B

व्याख्या: डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है। यह उद्देश्य उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ता है। बैठक में अधोसंरचना सुधार, विकास कार्यों की पूर्णता, विद्यार्थी योजनाओं की समीक्षा और तकनीकी क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान दिया गया।

3. बैठक के दौरान निम्नलिखित में से किस विषय की विशेष रूप से समीक्षा की गई?

- A. स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति और स्कूटी वितरण योजना
- B. केवल सड़क निर्माण परियोजनाएँ
- C. केवल कृषि सिंचाई योजनाएँ
- D. केवल मरुस्थलीय जिलों में पर्यटन विकास

उत्तर: A

व्याख्या: समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति और स्कूटी वितरण योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के कार्यों, तकनीकी शिक्षा से जुड़े समझौता ज्ञापनों, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी की कार्ययोजना, राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों और तकनीकी संस्थानों में स्टार्टअप प्रोत्साहन की भी समीक्षा की गई।

Rajasthan Approves Industrial Development Policy to Build a Global Industrial Hub



The Rajasthan Cabinet led by Chief Minister Bhajanlal Sharma has approved the Rajasthan Industrial Development Policy to keep the State in accordance with the vision of Viksit Rajasthan 2047. The policy's objective is to transform Rajasthan into a global industrial powerhouse by promoting various industrial sectors including semiconductors, data centres, defence manufacturing, renewable energy, circular economy, MSMEs, exports and local manufacturing. The Cabinet and Council of Ministers also discussed Pension reforms, the Vande Ganga Water Conservation Public Campaign, Electricity and Drinking Water Supply, Renewable Energy projects and Village Level Master Plans.

Key Highlights

- The Rajasthan Industrial Development Policy was approved to realize the vision of Viksit Rajasthan 2047.
- The policy is based on four strategic pillars: Green, Governance, Growth and Globalisation.
- The goal of the state is to grow its economy to 350 billion dollars by 2028–29.
- Special encouragement will be offered for semiconductors, Data Centres, Global Capability Centres and Defence Manufacturing.
- The promotion of renewable energy and circular economy will be done through the implementation of new industrial and resource recovery actions.
- Face authentication technology, which uses mobile devices, will be implemented to enable pensioners to submit annual life certificates.
- The Vande Ganga Water Conservation Public Campaign will be held between 25th May and 5th June.

Special Gram Sabhas will be held on 26 May for sanctioning of village master plans.

The government announced a surplus in electricity consumption in May. Cabinet and Council of Ministers decision making is of significant importance. The decision making of Cabinet and the Council of Ministers is an important matter.

Rajasthan Industrial Development Policy

- The policy's goal is to establish world class industrial infrastructure in Rajasthan.
- The participation of the private sector will be expanded for the development of industries.

More support will be provided to MSMEs, One District One Product and exports.

- Industries based on new technologies such as semiconductors, data centres, Global Capability Centres and defence manufacturing will be promoted.

Other traditional and employment generating activities like gems and jewellery, textile, tourism, handicrafts, agro-processing, dairy and logistics will also be supported.

- The policy is geared towards research and development, technology transfer, investment promotion and indigenous production.

Green Industry and Circular Economy

- Industrial production will be encouraged that is environmentally friendly.
- Policy support will be made available for renewable energy and circular economy.
- New schemes will be launched for Common Effluent Treatment Plant in RIICO and non-RIICO.
- Installing Integrated Resource Recovery Parks will be done.
- The Delhi-Mumbai Industrial Corridor will be developed into node based industrial parks.
- Consent will be given speedily, logistics connectivity will be encouraged, plug and play facilities and industrial infrastructure will be promoted.

Vande Ganga Water Conservation Public Campaign

- The campaign will be held from the Ganga Dussehra day (25th May) till the World Environment Day day (5th June).

- It will start with worship at water bodies, dams, ponds etc. followed by cleaning and de-silting of canals and drains.
- Cleanliness drive will be conducted, voluntary labour programmes and lamp-lighting will be held at district, block, gram panchayat, village and urban levels.
- The water chaupals would be held at the gram panchayat offices on water harvesting and water conservation works.
- Workshops will be held on drip, sprinkler and micro-irrigation systems.
- On 5 June, the Jal Gaurav Samman will be presented to exemplary water contributors like institutions, panchayats, urban bodies and 'water warriors'.

The pension and administrative reforms came later.

- Amendment in Rajasthan Civil Services Pension Rules, 1996 has been approved.
- Permanent disability certificates will now only be required for specially-abled children once.
- Mobile app-based face authentication will enable pensioners to submit life certificates every year.
- Authorisation to issue life certificate through SSO ID has also been given to the Non-gazetted employees except fourth class employees.
- Only one gazetted officer or respected person will be accepted for certification of families' pensions instead of two.
- The subject of electricity, drinking water and local governance is introduced. The topic of electricity, drinking water and local governance is introduced.
- The maximum demand for electricity was 16,487 MW in May on 20 May with an availability of 16,580 MW.
- The in-charge Ministers will keep monitoring, regularly, the drinking water and electricity supply in their districts.
- Any issues about electricity and drinking water called in on helpline 181 should be addressed within 24 hours.
- To approve draft master plans prepared under the Mukhyamantri Viksit Gram-Shahari Ward Campaign, special Gram Sabhas will be held in various parts of Rajasthan on 26 May.

Significance for Rajasthan

Such decisions are very important for the economy, government and welfare of the state of Rajasthan. The state can leverage advanced manufacturing, renewable energy and logistics and export-oriented businesses through the Industrial Development Policy. The water conservation campaign can be used to foster community involvement in water management, and pension reforms can enhance

pensioners' services. The local planning and timely public service delivery governance model are also reflected in the focus on master plans, electricity supply and drinking water.

Conclusion

The Cabinet decisions are a reflection of Rajasthan's efforts to bring together the three strands of industrial growth, green development, digital governance and public welfare. The importance of the Rajasthan Industrial Development Policy lies in the fact that it does not only encourage investment but also nurture local industries and generate employment opportunities as well. These decisions are in addition to water conservation, pension changes, projects for renewable energy and village planning, and all of these support the overall vision of Viksit Rajasthan 2047.

MCQs

1. The primary goal of Rajasthan Industrial Development Policy which was approved by the Cabinet is?

- A. To stop private investment in industrial areas
- B. To bring about a transformation in the lifestyle of the people of Rajasthan through new employment opportunities and financial independence.
- C. To concentrate only on the farming and irrigation schemes
- D. To replace the MSMEs which are small scale industries with only large scale industries

Answer: B

Explanation: Rajasthan Industrial Development Policy was approved with the aim to take Rajasthan as a global industrial hub in the wake of Viksit Rajasthan 2047 Vision. The policy targets advanced sectors – semiconductors, data centres, defence manufacturing, renewable energy, circular economy, MSMEs and exports, research and development, technology transfer and indigenous production.

2. Which of the following are the four pillars of Rajasthan Industrial Development Policy?

- A. Finance, Farming, Forest and Food
- B. Skill, Service, Security and Sustainability
- C. Green, Governance, Growth and Globalisation
- D. Water, Welfare, Women and Workforce

Answer: C

Explanation: The Rajasthan Industrial Development Policy is based on the four strategic pillars of Green, Governance, Growth and Globalisation. The pillars are indicative of the policy's emphasis on environmental-friendly industrial production, efficient governance, economic growth and global competitiveness. The policy also targets to make Rajasthan's economy 350 billion dollars by 2028-29.

3. What campaign is going to be held in Rajasthan from 25 May to 5 June?

- A. Mukhyamantri Viksit Gram-Shahari Ward Campaign
- B. Vande Ganga Water Conservation Public Campaign
- C. Har Ghar Udyog Campaign
- D. Rajasthan Export Promotion Campaign

Answer: B

Explanation: (Vande Ganga Water Conservation Public Campaign) World Environment Day, 5 June, is the last day of the campaign, and the first day is on Ganga Dussehra (25 May). This campaign will entail cleaning and de-silting of water bodies, water conservation initiatives, Water Chaupals, voluntary labour or labour in exchange for water, and recognition of excellent contributions through the Jal Gaurav Samman for water conservation and cleanliness in water bodies.

राजस्थान मंत्रिमण्डल के औद्योगिक नीति, पेंशन नियम, जल संरक्षण अभियान और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े निर्णय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान मंत्रिमण्डल बैठक में विकसित राजस्थान 2047 की दृष्टि के अनुरूप राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके तहत अर्धचालक, आँकड़ा केंद्र, रक्षा विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात तथा स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रिमण्डल और मंत्रिपरिषद की बैठकों में पेंशन सुधार, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, बिजली और पेयजल आपूर्ति, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं तथा ग्राम स्तरीय मास्टर प्लान पर भी चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को विकसित राजस्थान 2047 की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई।
- यह नीति 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है: हरित, शासन, वृद्धि और वैश्वीकरण।
- राज्य का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।
- अर्धचालक, आँकड़ा केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्र और रक्षा विनिर्माण को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।

- अक्षय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को नई औद्योगिक योजनाओं तथा संसाधन पुनर्प्राप्ति पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
- पेंशनभोगी मोबाइल अनुप्रयोग आधारित चेहरे की पहचान तकनीक से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से 5 जून तक संचालित होगा।
- ग्राम स्तरीय मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए 26 मई को विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएंगी।
- सरकार के अनुसार मई माह में बिजली की उपलब्धता अधिकतम मांग से अधिक रही।

मंत्रिमण्डल और मंत्रिपरिषद के प्रमुख निर्णय

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति

- इस नीति का उद्देश्य राजस्थान में विश्वस्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करना है।
- औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, एक जिला एक उत्पाद और निर्यात को अधिक सहयोग दिया जाएगा।
- अर्धचालक, आँकड़ा केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्र और रक्षा विनिर्माण जैसे नई तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, पर्यटन, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण, दुग्ध, और माल परिवहन जैसे पारंपरिक तथा रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- नीति अनुसंधान एवं विकास, तकनीक हस्तांतरण, निवेश संवर्धन और स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित है।

हरित उद्योग और चक्रीय अर्थव्यवस्था

- पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- अक्षय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को नीतिगत सहयोग मिलेगा।
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम क्षेत्रों और गैर-औद्योगिक निगम क्षेत्रों में साझा अपशिष्ट शोधन संयंत्रों के लिए नई योजनाएँ लाई जाएंगी।
- समेकित संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे में नोड आधारित औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।
- त्वरित स्वीकृति, माल परिवहन संपर्क, तत्काल उपयोग योग्य सुविधाएँ और औद्योगिक अधोसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान

- यह अभियान गंगा दशमी, 25 मई से विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून तक संचालित होगा।

- अभियान की शुरुआत नदियों, बांधों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों पर पूजन तथा नहरों और खालों की सफाई एवं गाद हटाने से होगी।
- जिला, खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और शहरी स्तर पर स्वच्छता अभियान, श्रमदान और दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल आयोजित कर जल संग्रहण और जल संरक्षण कार्यो पर चर्चा की जाएगी।
- बूंद-बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी।
- 5 जून को उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, पंचायतों, नगरीय निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा।

पेंशन और प्रशासनिक सुधार

- राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 में संशोधनों को मंजूरी दी गई।
- विशेष योग्यजन बच्चों को स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब केवल एक बार प्रस्तुत करना होगा।
- पेंशनभोगी मोबाइल अनुप्रयोग आधारित चेहरे की पहचान तकनीक से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अराजपत्रित कर्मचारियों को भी एकल प्रवेश पहचान के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार मिलेगा।
- पारिवारिक पेंशन प्रमाणीकरण के लिए अब दो के स्थान पर केवल एक राजपत्रित अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति का प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा।

बिजली, पेयजल और स्थानीय शासन

- मई माह में 20 मई को बिजली की अधिकतम मांग 16,487 मेगावाट रही, जबकि उपलब्धता 16,580 मेगावाट रही।
- प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में पेयजल और बिजली आपूर्ति की नियमित समीक्षा करेंगे।
- सहायता संख्या 181 पर प्राप्त बिजली और पेयजल संबंधी समस्याओं का समाधान 24 घंटे में सुनिश्चित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान के अंतर्गत तैयार प्रारूप मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए 26 मई को प्रदेशभर में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएंगी।

राजस्थान के लिए महत्त्व

ये निर्णय राजस्थान की अर्थव्यवस्था, शासन और जनकल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। औद्योगिक विकास नीति राज्य को उन्नत विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, माल परिवहन और निर्यात आधारित क्षेत्रों में मजबूत बना सकती है। जल संरक्षण अभियान जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगा, जबकि पेंशन सुधार पेंशनभोगियों के लिए सेवाओं को सरल बनाएंगे। मास्टर प्लान, बिजली आपूर्ति और पेयजल पर ध्यान स्थानीय योजना और समयबद्ध सार्वजनिक सेवा वितरण को दर्शाता है।

निष्कर्ष

मंत्रिमण्डल के ये निर्णय राजस्थान में औद्योगिक वृद्धि, हरित विकास, डिजिटल शासन और जनकल्याण को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास हैं। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति निवेश आकर्षित करने, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और रोजगार अवसर सृजित करने के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण, पेंशन सुधार, अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ और ग्राम स्तरीय योजना विकसित राजस्थान 2047 की व्यापक दृष्टि को मजबूत करते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत राजस्थान औद्योगिक विकास नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A. औद्योगिक क्षेत्रों में निजी निवेश को रोकना
- B. विकसित राजस्थान 2047 की दृष्टि के अनुरूप राजस्थान को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाना
- C. केवल कृषि और सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना
- D. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के स्थान पर केवल बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना

उत्तर: B

व्याख्या: राजस्थान औद्योगिक विकास नीति का उद्देश्य विकसित राजस्थान 2047 की दृष्टि के अनुरूप राजस्थान को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह नीति अर्धचालक, आँकड़ा केंद्र, रक्षा विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात, अनुसंधान एवं विकास, तकनीक हस्तांतरण और स्वदेशी उत्पादन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

2. राजस्थान औद्योगिक विकास नीति किन 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है?

- A. वित्त, कृषि, वन और खाद्य
- B. कौशल, सेवा, सुरक्षा और स्थिरता
- C. हरित, शासन, वृद्धि और वैश्वीकरण
- D. जल, कल्याण, महिला और कार्यबल

उत्तर: C

व्याख्या: राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है: हरित, शासन, वृद्धि और वैश्वीकरण। ये स्तंभ पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, प्रभावी शासन, आर्थिक विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाते हैं। नीति का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाना भी है।

3. राजस्थान में 25 मई से 5 जून तक कौन-सा अभियान संचालित किया जाएगा?

- A. मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान
- B. वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान
- C. हर घर उद्योग अभियान
- D. राजस्थान निर्यात संवर्धन अभियान

उत्तर: B

व्याख्या: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई को गंगा दशमी से शुरू होकर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तक संचालित होगा। इस अभियान में जल स्रोतों की सफाई, गाद हटाने, जल संरक्षण गतिविधियों, जल चौपाल, श्रमदान, सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्यशालाओं और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को जल गौरव सम्मान प्रदान करने जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।

Vande Ganga Water Conservation Campaign to Run from 25 May to 5 June 2026



Vande Ganga Water Conservation Public Campaign 2026 will run from 25 May to 5 June, 2026 as per the direction of the Rajasthan Government. The campaign will emphasize on environmental protection, rain water harvesting, cleanliness, water conservation, and public participation. The district level launch is to be held on 25 May, said District Collector Sandesh Nayak. Activities will be designed at district, block, gram panchayat, village and urban level. The campaign will involve

cleanliness drives at water sources, rivers, ponds and water harvesting structures as well as a voluntary labour initiative and a programme of lighting up the lamp.

Key Highlights

- The Vande Ganga Water Conservation Campaign 2026 is scheduled to take place from 25th May to 5th June 2026.
- The campaign will be dedicated to conservation of environment, rain water harvesting and cleanliness.

Activities will be organised at district, block, gram panchayat, village and urban levels.

- Cleanliness drives will be launched in the area of water sources, rivers, ponds and water harvesting structures with the support of voluntary labour and lamp-lighting.
- Social media will be used to promote the campaign.
- The programmes like Vande Ganga Prabhat Pheri, Kalash Yatra, Peepal worship and Peepal plantation will be organized.
- Water testing, raising the awareness of conserving water and cleaning the drinking water sources will be done.
- CSR workshops, water use audit and energy audit and information regarding green budget will also be given.

Public Participation and Awareness

- In order to involve the common man, Vande Ganga Prabhat Pheri and Kalash Yatra will be organised.
- Water saving public awareness programmes will be done.
- The campaign will be promoted using social media platforms.
- Awareness on water quality will be raised by water testing campaigns.
- The support of the voluntary organisations, donors and departments will be received for Vande Ganga Jal Seva activities.

Institutional and Community Programmes

- At local gaushalas, veterinary hospitals and dairy unions, there will be cleanliness drives organised to drive the will.
- With the district and block, discussions and seminars will be held.
- Media field visits will be organised to spread information about campaign activities.
- Vande Ganga Jal Seva will be organised at the railway stations, bus stands, grain markets and public places.
- Cleanliness and repair will take place in government establishments.

Significance for Rajasthan

The Vande Ganga Water Conservation Public Campaign 2026 is significant because it infuses water conservation with the participation of public, environmental protection, and local governance. Rajasthan is regularly plagued by water related issues, thus, rain water harvesting, water source cleaning and spreading awareness about water saving are very relevant. The campaign also encourages community action via gram panchayats, urban bodies, voluntary organisations, donors and government departments. The campaign is related to the following themes in the RAS exam: environment, governance, sustainable development, water management and citizen participation.

Conclusion

Vande Ganga Water Conservation Public Campaign 2026 is to create awareness and public participation for water conservation from May 25 to June 5. The campaign aims to improve the water management system at local level by utilizing the following activities and cleanliness drives: water testing, social media outreach, public events, audits and institutional participation. It embodies Rajasthan's commitment to sustainable water management and community-driven initiatives for environmental protection.

MCOs

1. When Vande Ganga Water Conservation Public Campaign 2026 which is scheduled to be held?

- A. 1 June to 15 June 2026
- B. 25 May to 5 June 2026
- C. 15 May to 25 May 2026
- D. 5 June to 25 June 2026

Answer: B

Explanation : Vande Ganga Water Conservation Public Campaign 2026 is to be carried out during 25 May to 5 June 2026. Various departments will conduct activities in these areas during this period at the district, block, gram panchayat, village and urban levels, such as environmental protection, rainwater harvesting, cleanliness, water conservation, public awareness and cleanliness of water sources.

2. Which of the following activities is related to Vande Ganga Water Conservation Campaign 2026?

- A. Cleaning of canals, drains and drinking water sources
- B. Distribution of industrial land only
- C. Construction of only private commercial buildings
- D. Closure of all water testing activities

Answer: A

Explanation : Cleaning of canals, drains, water bodies, drinking water sources are included in the campaign. It also involves worship on rivers, canals and dams, Catch the Rain activities, Jal Shakti Abhiyan, water testing, public awareness for water saving, Prabhat Pheri, Kalash Yatra, Peepal plantation, Voluntary labour and drives for cleanliness in public places.

3. Which of the following is the best explanation, from an exam point of view, for the importance of the campaign?

- A. It's associated with industrial investment and export promotion only.
- B. It deals only with urban transport and road safety.
- C. It is linked to water conservation, public involvement, environmental protection and local government.
- D. It applies only to changes of examination systems in schools.

Answer: C

Explanation: The campaign is important in the context of the RAS examination as it is related to water conservation, public participation and local governance and to environmental protection. It comprises activities at the district, block, gram panchayat, village and urban levels. It also takes into account departments, donors, voluntary organisations and citizens and is relevant for topics like sustainable development, water management, community participation etc.

वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 25 मई से 5 जून 2026 तक चलेगा

राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का आयोजन 25 मई से 5 जून 2026 तक किया जाएगा। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, स्वच्छता, जल संरक्षण और जनभागीदारी पर केंद्रित रहेगा। जिला कलक्टर संदेश नायक के अनुसार अभियान का जिला स्तरीय शुभारम्भ 25 मई को होगा। इसके अंतर्गत जिला, खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और

शहरी स्तर पर जल स्रोतों, नदियों, तालाबों और जल संग्रहण ढांचों पर स्वच्छता अभियान, श्रमदान और दीप प्रज्ज्वलन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 का आयोजन 25 मई से 5 जून 2026 तक होगा।
- अभियान पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण और स्वच्छता को समर्पित रहेगा।
- गतिविधियां जिला, खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और शहरी स्तर पर आयोजित की जाएंगी।
- जल स्रोतों, नदियों, तालाबों और जल संग्रहण ढांचों पर स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे।
- अभियान में श्रमदान और दीप प्रज्ज्वलन की गतिविधियां भी शामिल रहेंगी।
- अभियान का प्रचार-प्रसार सामाजिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा।
- वंदे गंगा प्रभात फेरी, कलश यात्रा, पीपल पूजन और पीपल पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- जल परीक्षण, जल बचत के लिए जन जागरूकता और पेयजल स्रोतों की सफाई की जाएगी।
- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यशाला, जल उपयोग अंकेक्षण, ऊर्जा अंकेक्षण और हरित बजट की जानकारी दी जाएगी।

अभियान के प्रमुख कार्य

जल संरक्षण और स्वच्छता

- नदियों, नहरों, बांधों और अन्य जल स्रोतों पर पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- नहरों और खालों की साफ-सफाई की जाएगी।
- कैच द रेन और जल शक्ति अभियान से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
- नए कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा।
- पेयजल स्रोतों की सफाई की जाएगी, ताकि आमजन को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके।

जनभागीदारी और जागरूकता

- आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए वंदे गंगा प्रभात फेरी और कलश यात्रा आयोजित की जाएगी।
- जल बचत के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- अभियान का प्रचार-प्रसार सामाजिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा।
- जल परीक्षण अभियान के माध्यम से जल गुणवत्ता को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
- स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों और विभागों के सहयोग से वंदे गंगा जल सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

संस्थागत और सामुदायिक कार्यक्रम

- स्थानीय गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों और दुग्ध संघों में स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे।
- जिला और खंड स्तर पर विचार-विमर्श तथा संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी।
- अभियान की गतिविधियों की जानकारी फैलाने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण कराए जाएंगे।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अनाज मंडी और सार्वजनिक स्थानों पर वंदे गंगा जल सेवा आयोजित की जाएगी।
- राजकीय भवनों की साफ-सफाई और मरम्मत से जुड़े कार्य किए जाएंगे।

राजस्थान के लिए महत्व

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जल संरक्षण को जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय शासन से जोड़ता है। राजस्थान में जल से जुड़ी चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं, इसलिए वर्षा जल संग्रहण, जल स्रोतों की सफाई और जल बचत के प्रति जागरूकता अत्यंत प्रासंगिक है। यह अभियान ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों और सरकारी विभागों के माध्यम से सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की दृष्टि से यह अभियान पर्यावरण, शासन, सतत विकास, जल प्रबंधन और नागरिक भागीदारी से जुड़ा हुआ है।

निष्कर्ष

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का उद्देश्य 25 मई से 5 जून तक जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और जनभागीदारी को बढ़ाना है। स्वच्छता अभियान, जल परीक्षण, सामाजिक माध्यमों से प्रचार-प्रसार, सार्वजनिक कार्यक्रम, अंकेक्षण और संस्थागत भागीदारी के माध्यम से यह अभियान स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन को मजबूत करने का प्रयास करता है। यह राजस्थान की सतत जल संरक्षण और समुदाय आधारित पर्यावरणीय कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 कब आयोजित किया जाएगा?

- A. 1 जून से 15 जून 2026
- B. 25 मई से 5 जून 2026
- C. 15 मई से 25 मई 2026
- D. 5 जून से 25 जून 2026

उत्तर: B

व्याख्या: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का आयोजन 25 मई से 5 जून 2026 तक किया जाएगा। इस अवधि में विभिन्न विभाग जिला, खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और शहरी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, स्वच्छता, जल संरक्षण, जन जागरूकता और जल स्रोतों की सफाई से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करेंगे।

2. निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 से संबंधित है?

- A. नहरों, खालों और पेयजल स्रोतों की साफ-सफाई
- B. केवल औद्योगिक भूमि का उपयोग
- C. केवल निजी व्यावसायिक भवनों का निर्माण
- D. सभी जल परीक्षण गतिविधियों को बंद करना

उत्तर: A

व्याख्या: इस अभियान में नहरों, खालों, जल स्रोतों और पेयजल स्रोतों की साफ-सफाई शामिल है। इसके साथ ही नदियों, नहरों और बांधों पर पूजन, कैच द रेन गतिविधियां, जल शक्ति अभियान, जल परीक्षण, जल बचत के लिए जन जागरूकता, प्रभात फेरी, कलश यात्रा, पीपल पौधारोपण, श्रमदान और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान भी आयोजित किए जाएंगे।

3. परीक्षा की दृष्टि से इस अभियान का सबसे उपयुक्त महत्व क्या है?

- A. यह केवल औद्योगिक निवेश और निर्यात प्रोत्साहन से जुड़ा है।
- B. यह केवल शहरी परिवहन और सड़क सुरक्षा से संबंधित है।
- C. यह जल संरक्षण, जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय शासन से जुड़ा है।
- D. यह केवल विद्यालय परीक्षा प्रणाली में बदलाव से संबंधित है।

उत्तर: C

व्याख्या: यह अभियान राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जल संरक्षण, जनभागीदारी, स्थानीय शासन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। इसमें जिला, खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और शहरी स्तर पर गतिविधियां शामिल हैं। इसमें विभागों, भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों की भागीदारी भी है, इसलिए यह सतत विकास, जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी जैसे विषयों के लिए प्रासंगिक है।